



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012020-215737
CG-DL-E-27012020-215737

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]
No. 321]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2020/माघ 4, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2020/MAGHA 4, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2020

का.आ. 353(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि ऐल्युमिना और ऐल्युमिनियम का विनिर्माण तथा बाक्साइट का उत्खनन में लगे उद्योगों की क्रमशः ऐसी सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 30 और 31 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित की जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने अंततः भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2621(अ), तारीख 24 जुलाई, 2019 द्वारा तारीख 24 जुलाई, 2019 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योगों को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में उक्त उद्योगों की लोक उपयोगी सेवा प्राप्ति को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योगों की सेवाओं को, 24 जनवरी, 2020 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस.11017/2/2011-आईआर (पीएल)]

वि. भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2020

S.O. 353(E).—In Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industries engaged in manufacturing of Alumina and Aluminium and mining of Bauxite which are covered under item 30 and 31, respectively, of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industries to be public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months from 24th July, 2019 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2621 (E), dated the 24th July, 2019;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industries for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the said industries to be a public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 24th January, 2020.

[F. No. S-11017/2/2011-IR (PL)]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.